दाखिले के लिए वसूल किये गये चन्दों के लिए स्कूल के विरुद्ध कानूनी मुकदमें दायर किये जा सकते हैं।

(ख) इन मामलों में कार्रवाई करना चूंकि राज्य सरकारों संघ शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आता है अत: यह सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

त्रिभाषा सूत्र का लागू किया जाना

1372. श्री **विश्वास राव रामराव पाटिल :**

श्री **अजीत जोगी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या त्रिभाषा-सूत्र देश भर में लागू किया जा रहा है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो किन-किन राज्यों में इस सूत्र को लागू नहीं किया जा रहा है और ऐसा न करने के लिए उन्होंने क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) तमिलनाडू को छोड़कर जो इस आधार पर द्विभाषा सूत्र कार्यान्वित कर रहा है, कि यह राज्य की नीति के अनुसार थी, सभी राज्यों ने सिद्धांतत: त्रिभाषा, सूत्र स्वीकार कर लिया है हालांकि कार्यान्वयन की सीमा हर राज्य में अलग-अलग है। 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश शामिल है, जहां संस्कृत को तीन भाषाओं में से एक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है।

(ग) त्रिभाषा-सूत्र के कार्यान्वयन के मामले में केन्द्रीय सरकार की भूमिका अनुशंसात्मक है तथा समय-समय पर राज्यों व संघ शासित प्रदेशों से त्रिभाषा सूत्र को शीघ्र व निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

1. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर व इसके मैसूर पटियाला, पुणे तथा भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा स्कूल स्तर पर भाषा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। सोलन व लखनऊ में उर्दू अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र भी उर्दू अध्यापन के लिए प्रभावशाली प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

2. केन्द्रीय सरकार अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

3. राज्यों को हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है।

Establishment of Botanical survey of India at Jodhpur

1373. SHRI B. L. PANWAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal for the establishment of a Botanical Survey of India at Jodhpur in Rajasthan: and

(b) if so, what is the financial involvement in the establishment of the said institute?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) and (b) The Botanical Survey of India have already an Arid Zone Circle at Jodhpur. Hence there is no question of any proposal being under consideration.